PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Sir, we have stout hearts.

MR. CHAIRMAN: We will go on to the oath-taking now.

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Sir, ...

MR. CHAIRMAN: Do you want to take the oath a second time as the Christians do?

DR. LOKESH CHANDRA (Nominated): I think the time has stopped, as the poet says.

MR. CHAIRMAN: Yes, oath-taking now.

MEMBER SWORN

SHRI P| ANBALAGAN (Tamil Nadu):

MR. CHAIRMAN: Now we will take up the questions.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Rise in prices of essential commodities

*81. SHRI INDRADEEP SINHA:
SHRI YOGENDRA SHARMA:†
SHRI BHUPESH GUPTA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government have initiated some measures recently after the presentation of Budget to check the rise in prices of essential commodities;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether these measures have yielded any results; if so, to what extent?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (c) Government is keeping continuous watch on the prices of essential commodities and as and when found necessary remedial measures are taken. During the past few months Government has taken a number of measures which are being continued. In the post-Budget period stock holding limits of both sugar as well as khandsari have been further reduced. Some restrictions have been imposed on khandsari producers with regard to stocks, sales and despatches of khandsari. The concerned Ministries have taken up with the concerned manufacturers and their associations to adjust suitably the prices of commodities for which excise concessions have been given in the Union Budget 1980-81. Further measures have been taken to make credit policy more restrictive. Of late, the weekly releases of imported edible oils to State Governments for sale through fair price shops have been stepped up.

While the overall price situation continues to be difficult, the measures taken will have an impact on the prices and availability of individual commodities.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, आपूर्ति मंत्रालय देश के जनसाधारण के लिए विपत्ति मंत्रालय हो गया है क्योंकि कोई भी महीना, कोई भी सप्ताह, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जबकि चीजों की कीमतें बढ़ती न जा रही हों और इस बढ़ती हुई कीमत से सारा देश परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है । हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि यह कांटीनुअस वाच रखे हुए हैं । यदि कांटीनुअस वाच का यह नतीजा है कि हर महीने कीमतें बढ़ें, हर

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Yogendra Sharma.

हफ्ते कीमतें बढ़ें तथा हर दिन कीमतें बढ़ें तो आप अपने कांटीनुयस वाच को बन्द कर दीजिए तो अच्छा है । आपने कहा कि हम रेमेडियल मेज़र्ज ले रहे हैं मगर उन तमाम रेमेडियल मेज़र्ज का नतीजा क्या है । मान्यवर, आल कमोडीटीज़ होल सेल प्राइस इंडेक्स 12.02 बढ़ गया है । बजट के बाद होल सेल इंडेक्स आफ आल कमोडीटीज़ बढ़ा है...

श्री रा० राममूर्ति : परसेन्टेज कितना है ?

श्री योगेन्द्र शर्मा : परसेंटेज तो निकाल लीजिए । 12.02 इतना बढ़ गया है बजट के बाद आल प्राइस कमोडीटीज़ प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ गया है । यह कहते हैं कि रेमेडियल मेज़र्ज ले रहे हैं । यदि उनके रेमेडियल मेज़र्ज का नतीजा यही है । यह वही बजट है जिसके बारे में एंटी इनफ्लेशनरी बजट कहा गया था उसके बाद भी 12.02 इंडेक्स बढ़ गया है । तो क्या मंत्री महोदय, अपने इन तमाम मेज़र्ज पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए ? मान्यवर, 12 जुलाई को ..

श्री सभापति : आप बराये मेहरबानी सवाल पूछिये ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं । उन्होंने कांटीनुयस वाच रखा और उस कांटीनुयस वाच का भी ऐसा नतीजा हुआ है तो यह वाच वे बन्द करें । जितने भी रेमेडियल मेज़र्ज उन्होंने लिए हैं उन सब का नतीजा यह है कि बजट के बाद 12.02 प्राइस इंडेक्स बढ़ गया । इस पूरे साल में 32 प्वाइंट बढ़ गए है । तो क्या मंत्री महोदय को यह नहीं समझना चाहिए कि अभी तक उन्होंने जो रेमेडियल मेज़र्ज लिए है वे काउंटर प्रोडक्टिव है, व उस उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक नहीं हैं बल्कि उनके जो मेज़र्ज हैं वे बढ़ती हुई कीमतों के प्रति...

श्री सदाशिव बागाईतकर : कोई मेज़र्ज हैं ही नही ?

श्री योगेन्द्र शर्मा : आप अगर बरा न माने तो...

श्री सभापति : मैं काहे को बुरा मानूं, मेरा क्या इसमें हाथ है...

श्री योगेन्द्र शर्मा : आप बुरा नहीं मानें । गरीब लोग एक सब्जी खाते हैं उसको अंग्रेजी में लेडीज़ फिंगर कहते हैं । हमको कोई एतराज नहीं है कि लेडीज़ फिंगर की कीमत इतनी बढ़ जाए कि वह अप्राप्य हो जाय । इसका कोई एतराज नही । मगर हम लोग उसको हिन्दी में या उर्दू में भिण्डी कहते है । उस भिण्डी की कीमत दिल्ली में वही है जो आम की है जिसको फलों का बादशाह कहते है । आम और भिण्डी दोनों की कीमत पर हमको एक कहावत याद आती है...

श्री पीलू मोदी : टके सेर भाजी, टके सेर खाजा ...

श्री योगेन्द्र शर्मा : अंधेर नगरी, चौपट राजा--टके सेर भाजी, टके सेर खाजा ।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिये ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं सवाल पूछ रहा हूं ।

श्री सभापति : मैंने अभी अभी बैठे बैठे यहां एक बार बना दिया है ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : सर, मेरा सवाल यह है कि भिंडी और आम दोनों की तुलना...

श्री सभापति : यह शेर जरा सुन लीजिए :

"इससे गर्ज नहीं है, कैसेहो चीनी सस्ती।"
बस एक ही फिकर है, हो जाय उनकी पस्ती।"

चलिए प्रश्न पूछिये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य की जो चिंताए हैं' हम सब उसमें भागीदार हैं और हम सबको इस तरह की चिंता है जैसे कि माननीय सदस्य ने यहां पर प्रदर्शित की है तथा हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं । अभी तक हमने कीमतों को रोकने में जितनी सफलता प्राप्त की हैं...

श्री सभापति : मिस्टर मिनिस्टर, आप जरा बताइए कि आपने क्या पाबंदियां लगायी हैं, क्या वसायल पैदा किये हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभापति जी, यदि आप प्रश्न पूछें...

श्री सभापति : उन्होंने प्रश्न पूछा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : नहीं, उन्होंने नहीं पूछा है । आप पूछें तो आपको मैं जवाब देता हूं ।

श्री सभापति : मैं तो नहीं पूछ रहा हूं । मगर वह जवाब आ जाय तो सबको इत्मीनान हो जाय ।

एक माननीय सदस्य : यह तो आप सबकी तरफ से पूछ रहे हैं...

(Interruptions)

श्री सभापति : मैं नहीं पूछता हूं । यदि आप जवाब न दें तो न दें ।

SHRI MANUBHAI PATEL: Let the hon. Minister read part (c) of the Question which reads: whether these measures have yielded any results and the Chairman is interpreting the same thing. He is not saying something new.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Whatever is printed in the Question has already been answered by me. Now I am answering supplementaries on the main question.

श्री सभापति : यह सवाल ऐसा हो जाता कि कोई दूसरा सवाल खड़ा नहीं हो सकता था । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर यदि कुछ जरा रोशनी डाल दें तो अच्छा रहता । मुझे कुछ नहीं पूछना है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जसा मैंने अपने उत्तर में कहा हम लोगों ने एक तो क्रेडिट पालिसी के द्वारा, दूसरी जो बहुत सी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी स्टाक लिमिट को कम करके तथा इसके साथ साथ उनका जो मूवमेंट है, उनकी फारवर्ड ट्रेडिंग है, इन सब पर प्रतिबंध लगाकर उसकी कीमतें रोकने का प्रयास किया है । हमको उसमें आंशिक सफलता मिली है, पूरी सफलता नहीं मिली है और पूरी सफलता मिलने में समय लगेगा । इस बजट से कीमतें घटनी चाहिएं थीं पर जिन लोगों के हाथ में व्यापार है उन लोगों को तो कीमतों से, जन हित से तथा जनता के सामने जितनी आवश्यकताएं हैं, उनकी प्राप्ति से मतलब नहीं है, वे तो पैसा कमाने के लिए कोशिश करते हैं । इसलिए उनके ऊपर जितना प्रतिबंध लगाकर, उनको

रोककर कीमतें घटाने का जो प्रयत्न हम कर सकते हैं, वह कर रहे हैं। राज्य प्रशासन का पूरा सहयोग लेकर हम इस काम को कर रहे हैं। राज्य प्रशासनों ने अपनी बहुत चुस्ती से इस काम को प्रारम्भ कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। पर सफलता एकदम या तत्काल नहीं आयेगी, धीरे धीरे आयेगी।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मेरा दूसरा सवाल है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि —पूरे देश को छोड़ दीजिए—देश की राजधानी दिल्ली में इंडस्ट्रियल वरकर्स का प्राईस इन्डेक्स बजट के बाद कितना बढ़ा है? मेरी जानकारी के मुताबिक मई में वह 407, जून में 412 और जुलाई में अनुमान किया जाता है कि 417 या 418 प्वाइंट हो जायेगा। आपके तमाम कदमों, तमाम कार्यवाहियों के बाद यदि यह नतीजा होता है तो फिर हम आपसे अनुरोध करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि आपको अपने तमाम कदमों पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस संबंध में मैं मंत्री महोदय की एक बात का समर्थन करूंगा कि हमारे देश का जो व्यापारी वर्ग है उसे जनता के सुख दुख की चिंता नहीं है, उसे सिर्फ एक बात की चिंता है कि कैसे वे अधिक से अधिक मुनाफा कमायें। यदि मंत्री महोदय ईमानदारी के साथ इस बात में विश्वास करते हैं तो क्यों नहीं तमाम एसेन्शियल कमोडीटीज के होलसेल के व्यापार को अपने हाथ में लेते हैं। उसके बाद हम और आप जो दो खेमों में हैं. .

(Interruptions)

श्री पीलू मोदी : प्राइस को दुगना करना है। Don't you know whatever as taken in hand, its price doubled:

श्री योगेन्द्र शर्मा : भई, वह तो भ्रष्टाचार की बात अलग है . . . (Interruptions) एक ही बात है कि व्यापारी लोगों को लाभ के अलावा कोई दूसरा कन्सिडरेशन नहीं है। जब तक उनके हाथ में स्टाक रहेगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए सरकार होल सेल ट्रेड अपने हाथ में ले ले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरे देश में जाल बिछावें और वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली तमाम दलों की सर्व-दलीय कमेटियों की देखरेख में काम करे

एक माननीय सदस्य : आपके साथी बड़े बेचैन हो रहे हैं...

(Interruptions)

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं तो मंत्री महोदय से उत्तर पूछ रहा हूं, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मान्यवर, यह जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें थोड़ी बहुत तो वृद्धि हुई है दिल्ली का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके फिगर्ज मेरे पास नहीं हैं। पर यदि सदस्य महोदय चाहेंगे तो मैं उसको लेकर सभा-पटल पर रख दूंगा जहां तक कि बजट के बाद कीमत बढ़ने का सवाल है, सदस्य महोदय यह कह रहे थे कि करीब 12 प्रतिशत बढ़ा है वह 12 प्रतिशत नहीं बढ़ा है, 5 प्रतिशत बढ़ा है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैंने इनसे बहुत ही साफ-साफ पूछा है कि क्या यह होलसेल ट्रेड को अपने हाथ में लेंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्टिब्यूशन सिस्टम करेंगे?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभापति महोदय, जहां तक मैं जानता हूं पालिसी

के प्रश्न क्वेश्चन आवर में नहीं उठाए जाते हैं यदि आप चाहें कि पालिसी मैटर डील करें तो अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन आवर में पालिसी मैटर के ऊपर हम कुछ नहीं कहते।

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Under what law it cannot be raised?

श्री सभापति : मुझे मालूम नहीं कि कितनी दूर क्वेश्चन आवर में जा सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : नियम यह है कि पालिसी मैटर क्वेश्चन आवर में नहीं पूछे जाते और न उनका जवाब दिया जाता है...

(*Interruptions*)

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: Sir, this is a relevant question. (*Interruptions*).

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Under what rule it cannot be raised?

SHRI YOGENDRA SHARMA: Please ask the hon. Minister under what rule of the Rules of Procedure the question that I have asked cannot be raised.

MR. CHAIRMAN: Just a minute. I will consult the Secretary-General.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Under the conditions of admissibility of questions.

MR. CHAIRMAN: It is mentioned here: "It shall not raise questions of policy too large to be dealt within the limits of an answer to a question".

SHRI G. C. BHATTACHARYA: It is not too large. टू लार्ज नहीं है, यह तो सीधा सा है। The answer is not complete. Even mismanagement is also...

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have to rule on it. There cannot be a single policy for all the commodities. Each commodity has its own angle. Rice has its own angle; cotton has its own angle; sugar has its own angle. Therefore, it is too large a question for answer by the Minister.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, my name is there.

MR. CHAIRMAN: I am sorry: Mr. Bhupesh Gupta's name is next on the list.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I am not asking about a policy matter. What is the use of showing the rules book in this manner? During the 11 years of Smt. Indira Gandhi's previous rule, prices were rising all the time—except for 10 months. During the Janata rule of two years or more, prices rose in one year and in the other year there was not much rise. But now I find that all past records of price rise have been broken. The rate of inflation today in India is among the highest in the world. In the developing countries, we are topping the list of inflationary countries that way. Now, how is it that despite the assurance of the Finance Minister that the Budget shall not have an inflationary effect on the prices, the prices have risen during the few months after the presentation of the Budget on an unprecedented scale? I would like to know what steps the Government is going to take and whether in this connection, they realise that unless certain basic policies—I am asking a policy question—are changed and drastically modified, the prices would not come down, and that in order to bring down the prices it is necessary not to give incentives to the monopolists, to the big profiteers, to businessmen and others who are engaged in speculation and so on, which the Government is doing at present, and also whether the Government is considering that in order to bring down the prices it is necessary to take physical possession

of certain essential stocks by nationalisation as well as by commandeering, if necessary. Is the Government considering the advisability of setting up or improving the public distribution network in the country which is far too inadequate for the needs of the situation? Sir, on all these counts, the Government policy not only is one of failure but one which encourages those who are responsible for price rise in the private sector...

MR. CHAIRMAN: Your question is over now.

SHRI BHUPESH GUPTA: Therefore, I want to know whether these steps are being taken.

MR. CHAIRMAN: Now your peroration has begun.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: It is a fact and I agree with the hon. Member that public distribution system in the country is far from adequate or far from satisfactory. We have started our endeavours to not only improve the public distribution system but to put it on a permanent footing and make it a permanent feature of our economy and our endeavours are to control the price and make essential commodities available to all sections of the people. The price rise that has been occasioned after the Budget, has really nothing to do with the Budget... (*Interruptions*).

SHRI BHUPESH GUPTA: My friend says, it has nothing to do with the Budget; but after the Budget, immediately the prices started rising.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, if you see the components of the price rise or the commodities which have contributed to this price rise, you would find that those commodities had not been touched in the Budget. Price rise, after the Budget, has been occasioned in the case of khandsari, sugar and gur, which have nothing to do with the Budget. Then there are other items, cereals, edible oils which have nothing to do with the Budget ..... (*Interruptions*). I will satisfy the hon. Member that the price rise that has occasioned after the Budget has really not much to do with the Budget, and, therefore... (*Interruptions*).

SHRI PILOO MODY: What about transport?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: If we start chasing reasons which are not really the causes of the price rise, then we will not be able to tackle the question. I agree with the hon. Member that price rise has been there...

SHRI BHUPESH GUPTA: It is causing a havoc.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Yes, and it is causing a heavoc in life. But the reasons are not which the hon. Member is giving. The reasons are the profiteering that is being indulged in, and the inadequacy of the public distribution system... (*Interruptions*).

SHRI G. C. BHATTACHARYA: How the public distribution system works when there is election? Then everybody gets everything. But after the votes were cast, there was nothing in the public distribution system.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Elections and public distribution have nothing to do with it. It is our commitment to the people that we shall fortify and improve the public distribution system and now we are going to do that and put it on such a footing that through this public distribution system, we will be able to control the prices effectively.

सैय्यद सिब्ते रज़ी : चेयरमैन साहब, ऐसा लग रहा है कि किसी साजिश की तहत इस बात की कोशिश की जा रही है कि देहर्स आने वाली सरकार को

बदनाम करने के लिए अवामी कैफियत से और अवामी हालात से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं । क्या माननीय मंत्री महोदय कोई सख्त कदम उन लोगों के खिलाफ उठाने जा रहे हैं जो अवाम की बेचैनियों से फायदा उठाना चाहते हैं ? मैं समझता हूं, अवाम की मजबूरियों से खेलने वालों को सबक सिखाने के ख्याल से सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और डी०आई०आर० और मीसा का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बाद भी अगर हमारे ट्रेडर्स में प्राफिटियरिंग बढ़ रही है और नयी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस से ज्यादा भी सख्त कदम उठाने की जरूरत हो तो उठाए जायं क्योंकि इस देश के अन्दर अवाम की तकलीफ से बढ कर...

(Interruptions)

श्री सभापति : सवाल तो कुछ है नहीं इस में । सवाल तो था नहीं, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : मीसा और डी आई आर के अन्दर कितने ट्रेडर्स को बन्द किया, यह बताएं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : एक सवाल था इस में ।

श्री सभापति : आप सवाल तो बताइए क्या था । सवाल तो था ही नहीं ।

(Interruptions)

SHRI PILOO MOOY: What question are you replying to?

SHRI SYED SIBTE RAZI: What action has been taken in this regard by the Government? That was my submission.

(Interruptions)

श्री विद्या चरण शुक्ल : जो बात माननीय सदस्य ने कही उस में बहुत सच्चाई है । उन्होंने पूछा यह है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ हम क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं और सख्त कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे मैं कहना चाहता हूं कि हम उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे । हमारे पास आज जो वर्तमान कानून हैं वे काफी सख्त और पक्के कानून हैं । उन में फेरबदल कर के जो थोड़ी-सी खामियां हैं उन को दूर करने के लिए एक संशोधन लाने वाले हैं, लाने का हम प्रयास कर रहे हैं । उन संशोधनों के बाद इन कानूनों का हम काफी कड़ाई से उपयोग करेंगे जिस से जो लोग आज गड़बड़ कर रहे हैं उन से सख्ती से पेश आ कर इन चीजों को रोक सकें ।

(Interruptions)

SHRI MANUBHAI PATEL: Sir, you promised me. *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: Just a minute. One by one and only one Member of a party—not too many as I have already said. Mr. Shahi, you will ask the question.

श्री रामेश्वर सिंह : यह हम लोगों के साथ अन्याय होगा ।

श्री सभापति : मेरे दिल में भी पचास सवाल हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : एक मिनट मेरी बात सुन लें । मान लीजिए किसी सदस्य के दिमाग में कोई बात नहीं आती है पूछने की और दूसरा सदस्य असली जगह पर उस को पकड़ सकता है तो आप उस को भी मौका दीजिए । अगर आप मुझ को एक मिनट का मौका दें तो मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह सरकार चल रही है...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए । मिस्टर शाही ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मंत्री जी ने यह कहा कि प्रोफीटियर्स की वजह से मंहगाई बढ़ती जा रही है तो क्या यह मान लिया जाय कि आप की सरकार प्रोफीटियर्स को कन्ट्रोल करने में नाकामयाब है? या आप उन से मिले हुए हैं और उन को कन्ट्रोल नहीं करना चाहते हैं। श्रीमन्, एक हफ्ते पहले दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नर ने दिल्ली के एक प्रोफीटियर की कम्पनी, जिस ने एडल्टरेशन किया था, जिस में उन का हिस्सा है, उस के खिलाफ मुकदमा था, उस मुकदमे को विदड्रा कर लिया है। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि आप की सरकार और आप का लेफ्टीनेंट गवर्नर इन एडल्टरेटर्स और प्रोफीटियर्स को सरक्षण दे रहे हैं।

श्री सभापति शाही जी, लेफ्टीनेंट गवर्नर यहां मौजूद नहीं हैं, वह जवाब नहीं दे सकते।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरा सवाल सीधा है...

श्री सभापति : आप उन का नाम छोड़ कर सवाल करिए।

SHRI BHUPESH GUPTA: He is responsible for that. I think he should reply.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आज से 7-8 साल पहले जिस समय आप की सरकार में धारिया साहब सप्लाई मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहा हूं। तीन साल तक लगातार वादा किया कि मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहा हूं। फिर वह सरकार चली गयी। जनता सरकार में भी वही उन के मिनिस्टर थे। उन्होंने दो साल तक लगातार वादा किया कि हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहे है, बीसियों बार उन्होंने इस हाउस में कहा, और वादा करते रहे कि दो महीने के बाद करेंगे, तीन महीने के बाद करेंगे। वह सरकार भी चली गयी। अब आप कह रहे है कि हम सोच रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वह भी चली जाएगी।

SHRI PILOO MODY: That is no answer to price control.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरा सीधा सवाल यह है कि आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कब तक फाइनल करेंगे? एक ही उस का जवाब है। जब तक आप व्यापारियों के हाथ से व्यापार छीन कर अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं चलेगा। आप कहते है कि व्यापारी लूट रहे हैं। मेरा सवाल है कि आप...

श्री सभापति : मिस्टर शाही, आधा घन्टा बीत गया, जहां हम थे वहीं हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति जी, माननीय सदस्य ने कई ऐसी बातें कही हैं कि जिन पर आपत्ति हो सकती है। पहली बात तो यह है कि यह समझते हैं और यह उन का आरोप है कि हम लोग उन लोगों से मिले हुए हैं कि जो कीमतें बढ़ा रहे हैं। यह सरासर गलत है। ऐसी बात पहले जब दूसरी सरकार थी तब हो सकती थी, पर अब ऐसी बात नहीं है... (*Interruptions*). अभी जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की बात आप ने कही, धारिया साहब जब कांग्रेस में थे तो वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चार्ज में नहीं थे कभी भी, पर जब वे जनता सरकार में मंत्री थे तब पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में उन्होंने जो कुछ किया उस को हम सुधारने में लगे हुए हैं ताकि जो बिगड़ी स्थिति है उस को कुछ सुधारा जा सके और उम्मीद है कि

हम जल्दी से जल्दी उस को ठीक कर सकेंगे ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Yadav.

SHRI MANUBHAI PATEL: Sir, you said one from each party.

MR. CHAIRMAN: I am taking one from each party.

SHRI MANUBHAI PATEL: It is an important question.

MR. CHAIRMAN: I know. I am giving the opportunity...

श्री रामेश्वर सिंह : आप ने यह क्वेश्चन लिया है और इसमें आप उन सदस्यों का मौका दीजिए जो सदस्य असली तथ्य को हाऊस के सामने रखना चाहते हों । आप को इस पर ध्यान देना है । सरकार बचना चाहती है ।

एक माननीय सदस्य : यह भाषण है, भाषण बंद करो ।

श्री सभापति : आप का भी वक्त आ रहा है । बैठे रहिये । मैं जानता हूं कि यह मामला ऐसा है कि इस में रोजाना झगड़ा शुरू होता है और एक बड़ी मुश्किल यह है कि कहा जाता था :

"मन तुरा हाजी बगोयम, तू मरा हाजी बगो"

मैं तुझे हाजी कहता हूं, तू मुझे हाजी कह, लेकिन उस के बाद एक शायर ने कह दिया :

"मन तुरा पाजी बगोयम, तू मरा पाजी बगो।"

श्री रामानन्द यादव : सभापति जी, इसमें संदेह नहीं कि प्राइसेज एशेंसियल कमोडीटीज की काफी बढ़ी हैं और इस में भी संदेह नहीं कि जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आयी इस देश के व्यापारियों ने, पूंजीपतियों ने, जमाखोरों ने, ब्लैक मार्केटियर्स ने और स्मगलर्स ने दिये जलाये अपने घरों पर और जनता सरकार के साथ कोआपरेट करना शुरू किया । इस लिये प्राइसेज उस समय कम बढ़ीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद से प्राइसेज बढ़ी इस लिये कि इस देश के जो व्यापारी थे, जो जमाखोर थे, स्मगलर्स थे, ब्लैक मार्केटियर्स थे वे सभी इस सरकार के साथ नान कोआपरेट कर रहे है और प्राइसेज बढ़ा रहे है । तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं (*Interruptions*). जरा सुन लीजिए (*Interruptions*) मेरा मेन क्वेश्चन यह है कि मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अब तक आप ने इस देश के ब्लैक मार्केटियर्स को, स्मगलर्स को डिटेन करने के लिये प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट बनाया । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने जमाखोरों, होल्डर्स के गोदामों पर छापा मार कर विभिन्न राज्यों में या दिल्ली में सरकार ने एशेंसियल कमोडिटीज को अपने कब्जे में ले कर वितरण प्रणाली सिस्टम के माध्यम से वितरित कराया है? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार यह भी बताये कि आज तक इस देश में एसेंशियल कमोडिटीज पैदा करने वाले, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले, इस देश के व्यापारियों को जो इस तरह के कार्य मे अपने को लगाये हुए हैं ऐसे कितनों को आप ने अरेस्ट कर के प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में जेल में बंद किया है । इस के आंकड़े इस हाउस के सामने आप रखें ।

MR. CHAIRMAN: Only two more questions I will allow on this. (*Interruptions*). Dr. Bhai Mahavir, you are always there.

श्री विद्या चरण शुक्ल : जिस पृष्ठभूमि में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है वह बहुत सही है । हम ने अभी तक 134 व्यक्तियों को नजरबंदी कानून के अन्तर्गत

गिरफ्तार किया है ; उन के यहां छापे डाल कर उन के यहां जो चीजें मिली आवश्यक वस्तुएं उन को निकाल कर बेचा भी और उन को जब्त किया । इस तरह की कार्यवाही आगे चल कर और भी ज्यादा तेजी से और सखती से हम चलाने वाले है ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Rameshwar Singh, and then another Member. That is all.

SHRI PILOO MODY: I also want to ask a question.

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन् सभापति जी, आपकी आज्ञा से जैसा अभी रामानन्द यादव जी ने भी कहा है और लोगों ने भी कहा है कि जनता पार्टी की सरकार में दामों की बढ़ोतरी हुई और जनता पार्टी के लोगों ने पूंजीपतियों से मिलकर यह काम किया है, यह उनका इल्जाम है। मेरा कहना यह है कि जनता पार्टी की सरकार में चीनी दो रुपये चार आना किलो बिकी और लोक दल की सरकार में चीनी दो रुपए बारह आना बिकी थी... (*Interruptions*) । जनता पार्टी और लोक दल की सरकार में जो चीनी के दामों में बढ़ोतरी हुई उसकी रेशियो मैंने आपको बता दी । जब से इनकी सरकार बनी है तब से चीनी आठ रुपये किलो बिक रही है । आज ही मैं कलकत्ता से आया हूं वहां पर चीनी नौ रुपया किलो बिक रही है यानी पिछली सरकार के चीनी के दामों की तुलना मे इस सरकार के चीनी के दामो मे पांच गुणा बढ़ोतरी है । मुझे डेफिनेट मालूम है कि दो सौ करोड़ रुपये इन्होंने विधान सभा के चुनावों के दौरान पूंजीपतियों से लिये . . .

(*Interruptions*)

यही कारण है कि आज पूंजीपतियो के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं । श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने बिरला साहब को और चीनी के मिल मालिकों मे से कितनों को आपने बंद किया है... (*Interruptions*) । मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि आपने उन लोगों को गिरफ्तार किया है या नही जो चीनी का प्रोडक्शन करते हैं और मिल के मालिक है? दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि दो सौ करोड़ रुपये लेकर और पूंजीपतियों से सांठगांठ करके दामों में हो रही बढ़ोतरी को रोकने में असफल रहे है?

(*Interruptions*)

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति जी, उल-जलूल आरोपों का उत्तर. . . .

श्री रामेश्वर सिंह : यह कहते हैं कि ऊल-जलूल सवाल आप करते है (*Interruptions*). आपकी सरकार भी बहुत जल्दी जाएगी अगर इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने की आपको आदत नही हैं. . .

(*Interruptions*)

श्री सभापति : इनको जवाब तो देने दीजिए ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य को मेरी बातें चुभनी नहीं चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि ऊल-जलूल आरोपों का मै उत्तर नहीं देता हू । दूसरी बात जो कही थी. . . .

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मेरा आरोप है कि पूंजीपतियों से, व्यापारियों से आपकी सरकार मिली हुई है यह आपकी पार्टी के लोग कहते है जो कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, रामानन्द यादव जी ने भी यहां कहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई आप कर रहे है? और क्या यह सही नही है कि 200 करोड रुपये मिल मालिको से ले कर विधान सभा के चुनावो में इस्तेमाल किये गये. . . (*Interruptions*)

श्री रामानन्द यादव : सभापति जी, बिल्कुल गलत बात है. . .

(*Interruptions*)

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह भी गलत बात है ।

श्री सभापति : उन्होंने और जो बातें कही थीं उनको छोड़ दें । उन्होंने जो एक सवाल पूछा है कि किसी मैन्युफेक्चरर को आपने पकड़ा हैं या नहीं पकड़ा है, किसी ट्रेड मैन को पकड़ा है या नहीं इसका जवाब आप दे दीजिए, बाकी का नहीं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इन्होंने एक बात कही थी....

श्री सभापति : यह तो 200 करोड़ की बजाय 400 करोड़ भी कह सकते हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इन्होने जो एक बात कही है उसको जरा साफ कर देना जरूरी है । इन्होंने पूछा है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान और लोक दल के शासन के दौरान चीनी फलां-फलां दाम पर बिकी आज इस दाम पर क्यों बिक रही है । मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ हमने किया था उसके कारण चीनी के दाम जनता शासन में कम रहे और आपने जो काम किया उसके कारण चीनी के दाम आज बढ़ रहे हैं । यही इसका उत्तर है । कार्रवाई के बारे में मैंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने इन लोगों को सहायता दी, जो जनता का शोषण कर रहे हैं ... (*Interruptions*)

SHRI RAMESHWAR SINGH: Sir,...

MR. CHAIRMAN: No more, Mr. Rameshwar Singh. Now the last question.

DR. BHAI MAHAVIR: At least one question should be permitted to us. Mr. Rameshwar Singh put many questions. Will you not permit us a single question?

श्री रामेश्वर सिंह : इनके हाथ से जब सत्ता हमारे हाथ में आई थी तब चीनी के दाम चार रुपये बारह आने किलो थी... (*Interruptions*) जनता राज में चीनी दो रुपये चार आने किलो बिकी... (*Interruptions*). । गलत बयान देकर यह सदन को गुमराह कर रहे हैं और मिल मालिकों से मिल कर ये लोग सरकार चलाना चाहते हैं । इनकी सांठ-गांठ पूंजीपतियों से है । इन्होंने बिरला को क्यों नहीं बन्द किया ? क्यों ये लोग मिल-मालिकों को बन्द नहीं कर रहे हैं ?

श्री सभापति : यह क्वेश्चन आवर है, कुश्ती लड़ने का दंगल नहीं है ।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, इनको समझदारी से सदन में जवाब देना चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Manubhai Patel.

SHRI MANUBHAI PATEL: Sir, according to the reply given by the hon. Minister, the present price rise is because of the wrong policies of the last Government. Now, their Government ruled for 11 years. And the Janata Government which came then brought down the prices within one year. Now, their Government has been there for the last seven months. And instead of any sign to bring down the prices, the hon. Minister has confessed himself in the previous reply that it is a matter of deep concern and anxiety that the prices of all the commodities are going up, in spite of the Essential Commodities Act and the strictest measures which they have in their armoury. Instead of taking measures to bring down the prices, the Government is taking strict measures, and perhaps brutal measures, against the innocent people who are trying to

ventilate their grievances against the price rise. Sir, the day before yesterday I was in Hubli; I had gone to Karnataka. There was a farmers' agitation there. The State Government there had given certain concessions and they had been withdrawn. But in the agitation which is going on at present, four persons were killed the day before and five persons were killed yesterday. This is an agitation of the middle class and the lower middle class against the price rise. So, instead of taking measures to curb the price rise, they are taking brutal measures of killing innocent people by firing on them.

MR. CHAIRMAN: But ...

SHRI MANUBHAI PATEL: Sir, it is connected with this. May I know from the hon. Minister whether, apart from taking proper measures to bring down the prices, the Government will assure us that any agitation to ventilate the feelings against price rise will not be curbed and people will not be shot down brutally? I would like to know whether that assurance will be given. That is the right of the people.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, the only question he has asked is whether we will suppress and curb any such anti-price rise movement. As long as the movement is peaceful and non-violent, we shall not do any of these things.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Dhabe. This is the last question because we have taken...

DR. BHAI MAHAVIR: Sir,...

MR. CHAIRMAN: No, Mr. Bhai Mahavir.

DR. BHAI MAHAVIR: None from our party. You have allowed five questions from one group and not even one from our group. At least one you may allow. Because we keep quiet, it should not go against us.

MR. CHAIRMAN: Not keeping quiet. I can count the number of times I have allowed you to ask questions. I will give you a question now, but I won't give you a question for another ten days.

DR. BHAI MAHAVIR: That should be the condition for all.

MR. CHAIRMAN: I am trying to do that.

DR. BHAI MAHAVIR: I will be happy if you lay down such a condition that any person who has asked a question will not be allowed to ask a question for the next 10 days.

MR. CHAIRMAN: I allowed you three questions yesterday.

SHRI S. W. DHABE: In order to curb price rise and to make available essential commodities at cheaper prices, this public distribution system has been introduced where levy sugar is sold at Rs. 2.85 per kilo, while in open market the prices are Rs. 7, Rs. 8 and so on. And in order to meet the shortage of sugar, the Government is importing sugar from outside. It has been announced by the Government in Bombay that the imported sugar will be sold at the fair price shops at Rs. 6.10. Is it the policy of the Government to sell sugar at a very high price at the fair price shops and give up the system of levy sugar so that the price of sugar will shoot up? I would like to know what the policy of the Government is about the imported sugar being sold at the fair price shops.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I do not know what statement the Maharashtra Government has made. Our policy regarding sale of sugar—both free market sale and levy sale of sugar—remains unchanged.

MR. CHAIRMAN: Question No. 82.

DR. BHAI MAHAVIR: Why do you neglect this group?

MR. CHAIRMAN: Question No. 82.

DR. BHAI MAHAVIR: I would like to know whether you do not

want us to participate in the proceedings.

MR. CHAIRMAN: I cannot have 244 Members participating in the proceedings in this one hour. My ruling in final. Question No. 82.

D. A. instalments due to the Central Government employees

*82. SHRI F. M. KHAN:
DR. RAFIQ ZAKARIA:†
SHRI N. K. P. SALVE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that another instalment of dearness allowance has become due to the Central Government employees w.e.f. 1st July, 1980, in addition to the one which became due from 1st May, 1980; and

(b) if so, by when Government propose to make payment of the two instalments?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) and(b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Government have already announced the payment of an instalment of dearness allowance to Central Government employees with effect from 1-5-1980. Orders for its payment are likely to be issued shortly. A further instalment of dearness allowance will become due for consideration only when the index average has crossed 368 points. The index figures so far received relate to the month of May, 1980. On the basis of these figures 12-monthly index average of the Consumer Price index works out to 366.50. The fact whether D.A. instalment will become due for consideration from 1-7-1980 will be known only sometime in August, 1980 when the index figures for June, 1980 are received from the Labour Bureau.

DR. RAFIQ ZAKARIA: Unfortunately due to the rise in prices of essential commodities, it is certain that another instalment of dearness allowance will become due in August, though the reply is rather vague about it. We know what the situation is. In view of that, I would like to know from the Finance Minister whether he has taken into consideration the repercussions of these repeated payment of dearness allowance to the Central Government employees on the ground that they become due as a result of rise in prices. There is no dispute as far as the payment of these instalments is concerned. But has he taken into consideration the repercussions of these on the finances of various States which are not powerful enough to hear these increasing burdens? As you know, the Finance Minister has been a very distinguished member of one of the most important State Governments and, therefore, I am sure he is aware of what happens as and when these instalments become due. . It is no use saying that the States can look after their finances. The Finance Minister is not only in charge of the Central exchequer, he is also the custodian of the financial management...

MR. CHAIRMAN: I think you have made your point.

DR. RAFIQ ZAKARIA... of the entire country. Therefore, I would like to know whether he is devising some machinery by which the limited resources of the various States are not adversely affected and their developmental programmes do not suffer in the process.

SHRI R. VENKTARAMAN: There are two issues involved in this question. One is payment of dearness allowance . .

MR. CHAIRMAN: Repeated instalments.

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Rafiq Zakaria.